विचार बिन्दु

कंजूसी मैं तुझे जानता हूँ! तू विनाश करने वाली और व्यथा देने वाली है। –अथर्ववेद

मतदान अवश्य कीजिए

लोकसभा चुनाव, 2024 के प्रथम चरण में जयपुर सहित राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल, 2024 को होगा। राजस्थान की शेष 13 सीटों के लिए मतदान 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होगा। देश में कुल सात चरणों में यह मतदान होगा, जिसकी मतगणना 4 जून को होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। विजय उस उम्मीदवार को मिलती है जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं। डाले गए मतों में से 30–35 प्रतिशत मत प्राप्त करके भी उम्मीदवार विजय प्राप्त कर लेते हैं। यदि इसे संसदीय क्षेत्र के कुल मतदाताओं के सन्दर्भ में देखा जाय तो यह 15–20 प्रतिशत ही रह जाता है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत लगभग 65–70 प्रतिशत रहता है। किसी भी क्षेत्र का सही प्रतिनिधि तब कहला सकता है जब संसदीय क्षेत्र के अधिकांश मतदाताओं का समर्थन उसे प्राप्त हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि अधिकाधिक मतदाता मतदान करें।

चुनाव आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के कई प्रकार के प्रयास हर चुनाव से पूर्व किए जाते हैं एवं मतदाताओं से अपील भी की जाती है कि वह अधिकाधिक संख्या में अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस बार का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वह इसमें विजय प्राप्त करें। यदि 30–35 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई उम्मीदवार जीत कर लोकसभा का सदस्य तो बन जाएगा किंतु यह कहना बहुत सही नहीं होगा कि वह उस क्षेत्र के मतदाताओं का पूरा प्रतिनिधित्व करता है।

शत प्रतिशत मतदान नहीं होने के कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण तो यह है कि कई लोग अपने काम में लगे रहते हैं और उनके नियोक्ता, विशेषकर निजी क्षेत्र के नियोक्ता, आदेशों के बावजूद भी अपने कर्मचारियों को मतदान करने के लिए आवश्यक अवकाश उपलब्ध नहीं कराते हैं। सबको पता होना चाहिए कि कोई भी नियोक्ता, किसी भी मतदाता को अपने मत देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है चाहे इसके लिए उसे काम हेतु, वैकल्पिक व्यवस्था ही क्यों न करनी पड़े। मतदाताओं की उदासीनता एवं निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण आज भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो अपने–अपने क्षेत्र में मतदान करने के योग्य हैं, किंतु मतदाता सूची में उनका नाम किसी न किसी कारण से अंकित नहीं है। इसलिए वह मतदान के अधिकार से वंचित रहते हैं। आशा की जानी चाहिए कि इस बार ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा। फर्जी मतदान की संभावना अधिक हो जाती है जब मतदाता सूची में कई ऐसे लोगों के नाम हों जो संबंधित क्षेत्र में नहीं रहते हैं अथवा कहीं बाहर पलायन कर गए हैं। इस बारे में वैसे तो सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं तथा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को पूर्णतया सचेत रहने की आवश्यकता होती है ताकि केवल ऐसे व्यक्ति का नाम ही मतदान सूची में अंकित किया जाए जो सामान्यत: किसी स्थान पर निवास करता है।

ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं जब कई लोग वोटर आईडी लिए मतदान केंद्र के बाहर खड़े होते हैं किंतु उन्हें मतदान करने नहीं दिया जाता सबके लिए जानना आवश्यक है की वोटर आईडी होने से मतदान का अधिकार नहीं मिलता अभी दो मतदान का अधिकार उसी को मिलता है इसका नाम उसे केंद्र की मतलब सूची में अंकित है वोटर आईडी पहचान के लिए आवश्यक काम में लिया जा सकता है। कई बार मतदाता इसलिए भी मतदान केंद्र तक नहीं जाते हैं कि उसे लगता है कि उसका जीवन तो वैसे ही चलना है, चाहे कोई भी जीते या हारे। उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। यह धारणा कतई सही नहीं है, क्योंकि देश का शासन उन लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, जिन्हें मतदाता सर्वाधिक समर्थन देगा।

यह उल्लेखनीय है कि भारत, उन गिने–चुने देशों में है जहां स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव से ही प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिल गया। इसमें पुरुष, महिला, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, सबको एक मत का समान अधिकार मिला। इसमें जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं है। विश्व के बहुत कम ऐसे देश हैं जहां स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव से ही सभी वयस्क लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया हो। कई चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह भी देखा गया है कि कई बार कम आयु के युवा मतदान में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। जब शिक्षित युवा अपने लोकतंत्र में इतनी कम रुचि दर्शाएंगे तो यह देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य नहीं करेगा।

यह सुझाव भी दिया गया है कि मतदान को अनिवार्य कर दिया जाए और मत न दे उसे दण्डित किया जाय। इसकी व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए एवं यह जानते हुए कि कई लोग चाहते हुए भी, परिस्थितिवश मतदान नहीं कर कर पाते, अभी तक मतदान को अनिवार्य बनाया नहीं गया है।

इस आलेख का मुख्य उद्देश्य इस बात को पाठकों तक पहुंचना है कि उनके लिए मतदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग मतदान करने के लिए इसलिए नहीं जाते हैं कि वह पहले ही यह धारणा बना लेते हैं कि विशेष व्यक्ति या दल जीतेगा एवं उनके एक वोट से क्या अंतर पड़ेगा। यह सोच लोकतांत्रिक अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि प्रत्येक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है यहां राजा की वह कहानी याद रखनी चाहिए जिससे सभी नागरिकों से एक लोटा दूध एक तालाब में डालने के लिए कहा गया था किंतु सब नहीं यह सोच लिया कि दूसरे तो दूध डालेंगे ही मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा और प्रात: काल पूरा तालाब केवल पानी से भर गया था। यदि जागरूक मतदाता जानकर, समझकर, विवेक का प्रयोग करके मतदान नहीं करेंगे तो वह एक प्रकार से उसे व्यक्ति या दल को जीतने में मदद करेंगे जिसे वह पसंद नहीं करते हैं। मतदान करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि पहले जिनके पक्ष में मतदान किया था क्या वे उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे थे? क्या उनके द्वारा किए गए वादे पूरे किए गए चाहे वे रोजगार के हों, सुरक्षा के हों, व्यवसाय में सरकारी दखल को कम करने के हों अथवा अन्य किसी प्रकार के हों। इस कसौटी पर कस कर यदि वे अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे तो वह अपने वोट का सही उपयोग कर पाएंगे।

> **चुनाव आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के कई प्रकार के प्रयास हर चुनाव से पूर्व किए जाते हैं एवं मतदाताओं से अपील भी की जाती है कि वह अधिकाधिक संख्या में अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस बार का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वह इसमें विजय प्राप्त करें।**

कई बार लोगों को यह कहते हुए भी सुना जाता है कि सारे उम्मीदवार एक जैसे हैं अत: किसी को भी वोट देने से कोई फायदा नहीं है और वह 'नोटा' का बटन दबा के आते हैं। नोटा या NOTA का अर्थ है None Of The Above)। यह सोच भी सही नहीं है क्योंकि नोटा का बटन दबाना एक प्रकार से व्यर्थ है। अब तक कानून में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि यदि 'नोटा' को सर्वाधिक मत मिले तो उस क्षेत्र में नए उम्मीदवारों के बीच के लिए पुन: मतदान होगा।

मतदाताओं को इस ओर भी सचेत रहना है कि उनके मत का अंकन अवश्य हो जाए। इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा कई बार जानकारी उपलब्ध करायी गई, किंतु मेरा यह अनुभव है कि कई मतदाता समुचित जानकारी के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि ई वी एम में उनका मत रिकार्ड हुआ है या नहीं? ऐसी स्थिति में कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी किसी मतदान एजेंट के दबाव में या उसकी मिलीभगत से किसी और उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकन कर सकता है। प्रत्येक मतदाता को ध्यान रखना चाहिए कि वह जब मतदान कक्ष में पहुंच जाता है एवं अपना बटन दबाता है उसके पूर्व वोटिंग मशीन को सक्रिय करने का बटन पीठासीन अधिकारी के पास होता है। जब मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के समक्ष बटन दबा दे, तो उसके बाद एक 'बीप' की आवाज सुनाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि उसके द्वारा दिया गया मत रिकॉर्ड हो गया है। प्रत्येक मतदाता को यह देखना चाहिए कि वह मशीन के सक्रिय होने के बाद ही बटन दबाये। और यह सुनिश्चित करे कि मत के अंकन करने के बाद बीप की आवाज सुनाई दी है।

जब से 'विविपेट' Voter Verified Paper Audit Trail) की प्रक्रिया लागू की गई है, मतदाता जिस उम्मीदवार के पक्ष में मत देगा उससे संबंधित चुनाव चिन्ह पर्ची पर अंकित होकर के नीचे डिब्बे में गिरेगी। गिरने से पहले वीवीपीएटी मशीन के अंदर के बल्ब के प्रकाश में 7 सेकंड तक मतदाता उसको देख सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में उसने मतदान किया है उसी की पर्ची उसमें छपी है अथवा नहीं। किसी प्रकार का अन्तर होने पर वह मतदान अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पाठकों के लिए जानना रुचिकर होगा कि मतगणना यूनिट वी वी पेट मशीन से जुड़ी होती है। आपने ballot यूनिट पर किसी भी बटन को दबाया हो, जब तक वही अंकन वी वी पेट मशीन के माध्यम से नहीं दिखाई देगा, तब तक रिकॉर्ड सही नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस उम्मीदवार को मतदाता मत देना चाहे, उसी के पक्ष में मत का अंकन हो और जिसके पक्ष में अंकन हो वही रिकॉर्ड में जाए और जो रिकॉर्ड में जाए उसी की गिनती हो। यदि यह प्रक्रिया पूरी तरह शत प्रतिशत सही नहीं होगी तो ई वी एम के बारे में शंकाएं व्यक्त की जाती रहेंगी जैसी की जाती रही हैं।

कई सामाजिक संगठनों द्वारा इस बात की मांग लंबे समय से की जाती रही है कि चुनाव कागज के मत पत्रों के माध्यम से ही करना उचित है क्योंकि इससे मतदाता को विश्वास अधिक होता है। इस संबंध में कई याचिकाएं भी माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई हैं किंतु अब तक इस बारे में कोई निर्णय अंतिम रूप से नहीं हो पाया है। अत: वर्तमान लोकसभा चुनाव में तो यही संभावना है कि ईवीएम का ही प्रयोग होगा और वी वी पेट मशीन लगाई जाएगी। यह संभव है उच्चतम न्यायालय, शत शत प्रतिशत वीवीपीएटी पर्चियां की गिनती करके उसका मिलान मशीन में अंकित परिणाम से करने का आदेश दे। यदि ऐसा हुआ तो फिर लगभग वही स्थिति होगी जिस प्रकार की मत पत्रों के माध्यम से चुनाव करने पर होती थी। ऐसा वर्तमान में इसलिए नहीं किया जाता है कि ऐसा करने पर परिणाम में समय लगेगा और परिणाम एक या दो दिन बाद में आएगा। मतदाता का विश्वास बनाए रखने के लिए इस प्रकार का विलंब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव वैसे ही लगभग डेढ़ महीने तक चलेगा। इस कारण एक–दो दिन का विलंब महत्वहीन है। यह उल्लेखनीय है कि कई विकसित देशों में जहां ई वी एम का प्रयोग प्रारंभ हुआ था वहां पुन: मत पत्रों के आधार पर चुनाव होने लगा है। क्योंकि मशीन के साथ छेड़छाड़ की संभावना तकनीकी विकास के कारण पहले से कहीं अधिक हो गई है।

उपरोक्त सारी बातें तो न्यायालय के देखने की हैं। जहां तक मतदाता का प्रश्न है, उसे तो केवल एक काम करना है कि मतदान के दिन उसे अपने केंद्र पर जाकर अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान अवश्य करना है। लोकतंत्र के मूल में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मतदाताओं की है।

इस आलेख के माध्यम से जयपुर के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वे 19 अप्रैल को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी दबाव एवं प्रलोभन के करें। ऐसा करते समय उन्हें जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर सोचना है और यह देखना है कि सबसे सशक्त रूप से एवं निष्पक्ष रूप से उनके हितों का संरक्षण कौन सा उम्मीदवार कर पाएगा? आपके निर्णय से यह तय होगा कि आगामी पांच वर्ष तक आपको किस प्रकार का शासन मिलेगा एवं आपका प्रतिनिधि किस प्रकार का होगा? इस समय की उदासीनता या निष्क्रियता का दुष्परिणाम आपको 5 वर्ष तक झेलना पड़ेगा। आशा है अपने आलस्य का परित्याग करते हुए एवं कुछ असुविधा उठाते हुए भी सभी मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे। जो पाठक इसे पढ़ रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वे अपने संपर्क में आने वाले सभी मतदाताओं को मतदान हेतु आग्रह करें क्योंकि, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है।

भारत के मतदाताओं ने पूर्व में कई बार अपने निर्णय से अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक और परिपक्वता का परिचय दिया है। आशा है इस बार भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अपेक्षा यही है कि आगामी चरण में होने वाले चुनाव में राजस्थान और भारत के सभी मतदाता उसमें भाग लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, शुभकामनाएं।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

आखिर इस मर्ज की दवा क्या है...

अविनाश जोशी

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मुख्य रूप से एक आपदा है क्योंकि चिकित्सा संस्थानों के द्वारा प्राप्त कम धन के कारण इनकी स्थिति खराब है। वास्तव में, नए औद्योगिक देशों में और यहाँ तक कि ब्रिक्स देशों में भी, स्वास्थ्य देखभाल पर भारत का प्रति व्यक्ति खर्च बहुत ही निराशाजनक है। भारत में वार्षिक प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करीब 75 डॉलर है। जबकि चीन की प्रति व्यक्ति वार्षिक 420 डॉलर तथा दक्षिण अफ्रीका की 570 डॉलर, रुस की 949 डॉलर और ब्राजील की 947 डॉलर है तथा ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 4003 अमेरिकी डॉलर है, जापान में 4150 डॉलर तथा अमेरिका में 9451 डालर है। यदि यह आँकड़े देश की स्वास्थ्य सेवा की निराश और दु:खी स्थिति को प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो आइये देखते हैं कि सरकार इनसे निपटने के लिए क्या करती है।

ऐसी संभावना है कि भारत में सार्वजनिक चिकित्सा केन्द्रों पर उपचार करवाने में एक मरीज को जितना खर्च करना पड़ता है उससे 800 गुना अधिक निजी अस्पतालों और चिकित्सा केन्द्रों में खर्च करना पड़ता है। इसके बावजूद, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग निजी चिकित्सकों और चिकित्सा सेवाओं को ज्यादा पसंद करते हैं। निजी चिकित्सा केन्द्र अपनी व्यय का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अपनी सेवाओं पर ही लगा देते हैं, जबकि सरकार ने लगभग अपने स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं के खर्च को स्थिर कर रखा है। एक राष्ट्र के रूप में, हम सामाजिक सुरक्षा और राज्य द्वारा प्रायोजित चिकित्सा सहायता से बहुत दूर हैं, लेकिन बढ़ते शुल्कों के कारण अधिकांश भारतीय गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से काफी दूर हैं।

अगस्त 2017 में, नीति आयोग ने टियर और टियर शहरों में चिकित्सा सुविधाओं और अस्पतालों का निजीकरण करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय अस्पतालों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं किए गए उपचारों के लिए रोगियों से इसकी वसूली करने की अनुमति देगा। 2013–14 के अनुसार, सरकारी अस्पतालों पर लगभग 8,193 करोड़ रुपये के खर्च के साथ–साथ निजी अस्पतालों पर लगभग 64,628 करोड़ रुपये कुल खर्च का अनुमान लगाया गया था। इसकी वजह से आम आदमी अधिक पीड़ित है। हृदय रोग, कैंसर, फेफड़े के रोगों और जीवन शैली से संबंधित बीमारियों से, मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए उपचार और दवा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

यह सही समय है कि भारत सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों पर अपना ध्यान दें। अमेरिका में देश के लोगों की राहत के लिए ओबामा केयर की शुरूआत ने अमेरिका के लोगों के लिए बहुत आराम प्रदान किया था। यहाँ तक कि ट्रम्प प्रशासन ओबामा केयर को निरस्त करने के लिए तैयार है, लेकिन देश के लोग नए प्रस्तावित नियमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत को भी ऐसे ही कुछ गंभीर स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों की आवश्यकता है, जो भारत के लोगों को अनुचित चिकित्सा तथा इसके खर्चों से राहत दे सके। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलाज में कितना अंतर होता है, इसका अंदाजा इस खबर को पढ़कर बखूबी लगाया जा सकता है। यदि जयपुर के किसी व्यक्ति को अचानक से मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो उसके सामने क्या विकल्प हैं। पहला अपने बगल का कोई निजी अस्पताल। यदि मरीज को वहां से रेफर करना है तो उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला एस एम एस तो दूसरा प्राइवेट अस्पताल। एस एम एस में भीड़ इतनी ज्यादा है कि परिजन सोच में पड़ जाते हैं कि वहां पर इलाज मिलेगा कि नहीं। आखिर में वे प्राइवेट अस्पताल का रास्ता चुनते हैं। वहां इलाज मिलता है और उसकी पूरी कीमत भी चुकानी होती है। कई बार यह खर्च मरीज की हैसियत से ज्यादा और इतना मनमाना होता है कि विवाद भी होते हैं। प्रशासन या सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे मनमर्जी के रेट पर लगाम कसी जा सके। इसका फायदा प्राइवेट अस्पताल उठा रहे हैं। हाल ही में आई नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट भी बताती है कि सरकारी अस्पतालों के मुकाबले प्राइवेट अस्पताल औसतन चार गुना ज्यादा खर्च पर इलाज देते हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक रेट आउट आफ कंट्रोल होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला सरकारी अस्पतालों की संख्या का कम होना। जो हैं, वे पहले से बोझ से दबे हैं। दूसरा कैंसर व कार्डियोवस्कुलर बीमारियों का इलाज सिर्फ मेडिकल कालेज व टर्शरी केयर सेंटर में उपलब्ध है। यदि सरकार चाहे तो ऐसे इलाज सिविल अस्पताल में भी शुरू हो सकते हैं। यदि किसी को कार्डियो की इमरजेंसी हो तो पीजीआई में भर्ती कराने में ही पसीने छूट जाते है, जबकि प्राइवेट में आते ही तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। दूसरा कारण प्राइवेट हॉस्पिटलों पर कोई रूल रेगुलेशन का न होना। सरकार या प्रशासन के पास ऐसा कोई नियम नहीं है, जिससे वे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट को कंट्रोल कर पाएं। दो साल पहले सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर कैंसर की दवाओं के रेट 60 प्रतिशत कम किए गए थे। यदि ऐसा हो सकता है तो प्राइवेट हास्पिटल्स के रेट पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता। इलाज का खर्च काफी महंगा है। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। सवाल यह है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं। केंद्र व राज्य सरकारे हेल्थ पर अपनी कुल जीडीपी का मात्र 1.2 प्रतिशत रुपये खर्च करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्वनमेंट हेल्थ की क्या स्थिति है।

देश के 75 प्रतिशत मरीज प्राइवेट हास्पिटल पर निर्भर है। चंडीगढ़ के प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं मिलती है। उपकरण से लेकर स्टाफ का खरचा खुद हॉस्पिटल को उठाना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वे अपने सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाएं। यदि सुविधाएं होंगी तो मरीज क्यों प्राइवेट में आएगा। हमारे शहर में सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया हैं। यदि इन अस्पतालों को सुधार लिया जाए तो मरीज प्राइवेट क्यों जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लगाम कसने के लिए क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करना होगा।

बीमारी का निदान तो एक ही है, जो कोई डॉक्टर थोड़ा या ज्यादा लालची है तो टेस्ट लिखेगा, अपनी पसंद की लैब बताएगा और कमीशन खायेगा। फिर रिपोर्ट्स देखेगा, अपनी पसंद की कम्पनी की दवाइयां लिखेगा, एक–दो दवाइयां ज्यादा लिख देगा, ताकत की दवा के नाम पर। पसंद की कम्पनी उसे गिफ्ट देती है। वरना डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो अनुभव से बीमारी का अंदाजा तो हो ही जाता है, कारगर दवा लिखकर इलाज कर सकता है। बाकी आप खुद समझ लें। प्राइवेट अस्पताल के खर्चे निकाल कर प्रॉफिट में लाने के हथकंडे तो अपनाने ही होंगे। सेवाभाव आजकल देखने को नहीं मिलता है।

भारत, 132 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ विश्व के सबसे बड़े देश चीन को पछाड़ने की तैयारी में है। हमारी आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर आप इस कथन से स्पष्ट नहीं है, तो इस पर विचार करें। भारत की आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम है और लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र की आबादी का है। अगले 3 वर्षों में 2020 तक, भारतीय लोगों की औसत उम्र 29 साल होगी, जबकि एक चीनी की औसत आयु 37 साल तथा जापानी लोगों की औसत आयु लगभग 48 वर्ष होगी। युवा भारत उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा है, लेकिन भारत में मध्यम आयु वर्ग के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं।

–अविनाश जोशी,
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

कांग्रेस और आर.एल.पी. के 100 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा

बिदियाद माली सैनी समाज के 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी

बिदियाद, (नीसं)। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने परबतसर क्षेत्र के ग्राम बिदियाद में जनसंपर्क किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के छीतर बड़ारडा के साथ करीब पचास कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को समर्थन देकर भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं इस दौरान माली समाज के करीब पचास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया।

इसके बाद मिर्धा ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और देश का हर वर्ग प्रधानमंत्री के साथ जुटा हुआ है, इसलिए परबतसर की जनता भी इस बार मोदी जी के सपने

> **■ भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने परबतसर के बिदियाद में जनसंपर्क किया**

को साकार करने के लिए अपना योगदान देगी और मोदी सरकार 400 पार की सरकार बनेगी।

इस मौके पर पूर्व विधायक परबतसर राकेश मेघवाल, पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, नगर पालिकाध्यक्ष ओमप्रकाश सेन, पूर्व सरपंच गुर्जर नेता जयराम गुर्जर, भाजपा महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनिता रांदड, जिला उपाध्यक्ष राजश्री खण्डेलवाल, रामकरण किरड़ोलिया, एरिया एसोसिएशन अध्यक्ष भागुराम आंवला, परबतसर विधानसभा संयोजक मूलचंद चिताई, पूर्व सरपंच मोहनराम मुंदलिया आदि उपस्थित थे।

भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने परबतसर क्षेत्र के ग्राम बिदियाद में जनसभायें की और समर्थन मांगा।

शेखावाटी को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा : घनश्याम तिवाड़ी

झुंझुनूं, (निसं)। चुनावी मौसम में यमुना नहर का पानी शेखावाटी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सोमवार को इस मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने झुंझुनूं में प्रेसवार्ता की। इस मौके पर घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि वे जब पहली बार राज्यसभा में गए तो उन्होंने उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सहयोग से तीन बार यमुना के पानी का प्रश्न उठाया, जिसके बाद ना केवल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, बल्कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से चार

> **■ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने झुंझुनूं में प्रेसवार्ता की**

पाइप लाइनों के जरिए पानी लाने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार केंद्र, हरियाणा और राजस्थान अब शेखावाटी की प्यास बुझाएगी। इस बार शेखावाटी का वोट, पानी के लिए होगा। क्योंकि यदि भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे तो वह इस योजना को मूर्त रूप देने में सहयोगी साबित होंगे। यदि दूसरे लोग पहुंच गए तो वो सो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। जिससे योजना प्रभावित होगी।

तिवाड़ी ने कहा कि हालांकि भाजपा संकल्प ले चुकी है कि यमुना का पानी शेखावाटी में हर हाल में लाया जाएगा। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग डीपीआर और एमओयू को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि शेखावाटी को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारीलाल सैनी समेत अन्य मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 1917 क्यूसेक पानी यमुना से और 1500 क्यूसेक पानी कुंभाराम से मिलेगा, यदि 4000 क्यूसेक पानी शेखावाटी को मिल जाता है तो सिंचाई और पीने के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।

डमी परीक्षार्थी को बैठाने वाला मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर की सूरसागर पुलिस ने इस साल जनवरी में आयोजित डीईएल–ईडी परीक्षा में पकड़े गए डमी परीक्षार्थी के बाद अब मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया है। मूल अभ्यर्थी ने अपनी परिचित को परीक्षा में फोटो में कांट–छांट कर बिठाया था। जिस पर परीक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

थानाधिकारी मांगीलाल विश्नोई ने बताया कि इस साल जनवरी में डीईएल–ईडी की भर्ती परीक्षा का आयोजन कालीबेरी सूरसागर में हुआ था। जिसका एक सेंटर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आया था। जहां परीक्षा भवन में एक फ र्जी परीक्षार्थी

> **■ इस साल जनवरी में आयोजित हुई थी डीईएल-ईडी परीक्षा**

फलोदी सांवरीज के सुभाष गोदारा को पकड़ा गया था। वह मूल अभ्यर्थी विकास विश्नोई के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया था। फोटो मिलान में वह डमी परीक्षार्थी पाया गया था। जिस पर प्रधानाचार्य गायत्री बोहरा की तरफ से राजस्थान परीक्षा अधिनियम में केस दर्ज कराया गया था। थानाधिकारी मांगीलाल विश्नोई ने बताया कि अब मूल अभ्यर्थी आरटीओ विद्यानगर भदवासिया निवासी विकास पुत्र निंबाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

राशिफल मंगलवार 16 अप्रेल, 2024

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, पुष्य नक्षत्र बुधवार प्रात: 5:16 तक, धृति योग रात्रि 11:16 तक, बव करण दिन 1:24 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–मेष, चन्द्रमा–कर्क, मंगल–कुम्भ, बुध–मीन, गुरू–मेष, शुक्र–मीन, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज दुर्गाष्टमी, महाष्टमी, अशोकाष्टमी, भौमाष्टमी और अन्नपूर्णा पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:21 से 10:55 तक, लाभ–अमृत 10:55 से 2:02 तक, शुभ 3:36 से 5:10 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:06, सूर्यास्त 6:48

मेष
घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

कर्क
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर–परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव–प्रभुत्व बढ़ेगा।

सिंह
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक विवादों से से राहत मिल सकती है।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मकर
घर–परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ
स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच–विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।